

समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक..... /गो०

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज
कार्य०अभि०, भवन प्र०, मधेपुरा
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय : नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-185396,
दिनांक-16-05-2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत निदेश दिया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

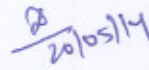
विश्वासभाजन

ह०/-

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....1481..... /गो०, मधेपुरा, दिनांक.....20/05/2014.....

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


20/05/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित
किया
जाता
है

प्रमाणित किया जाता है

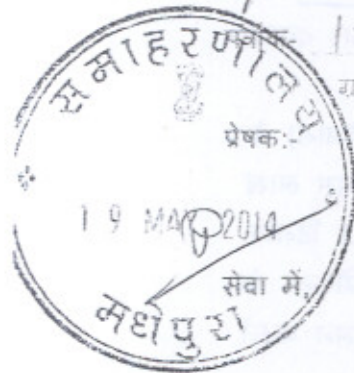
प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है
कि यह प्रमाणित किया जाता है

23666

वैरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा ~~वि०~~

DDC

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग



185396 /ग्रा0वि0वि0,
ग्रा0वि03/स्था013-01/14

पटना, दिनांक- 16/05/14

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

DDC /SDMs
EE जवान /AU BDOs
स्वयं प्रेम
As per rule शीर्षक को

19/05/14

विषय:- नयी तकनीक से निर्मित होने वाले प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवनों एवं परिसर विकास के लिए किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

राज्य में संप्रति 534 प्रखंड हैं इसमें से 137 नवसृजित प्रखंड जिनके कार्यालय भवन एवं आवास नहीं है । इन 137 नवसृजित एवं 1 बोधगया प्रखंड कुल 138 प्रखंडों के प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण कक्ष, आवास, निर्माण एवं परिसर विकास हेतु प्रति प्रखंड कार्यालय सह आवास यूनिट हेतु 538.84 लाख रुपये तथा आवास यूनिट हेतु 351.00 लाख रुपये पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

2. भवन निर्माण विभाग द्वारा कुल 38 प्रखंडों के लिए 29829.00 लाख (दो अरब अठ्ठावन करोड़ उन्नीस लाख) रुपये के प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में जापांक 111963 दिनांक 28.06.12 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-3 में मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 051- निर्माण उप मुख्य शीर्ष-01 कार्यालय भवन समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विपत्र कोड पी0-4059010510117 के अन्तर्गत 75000000.00 (पचहत्तर करोड़) रुपये मात्र का उपबंध किया गया था ।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-3 में मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 051- निर्माण उप मुख्य शीर्ष-01 कार्यालय भवन समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विपत्र कोड पी0-4059010510117 के अन्तर्गत 24.50.00,000.00 (चौबीस करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र का उपबंध किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस हेतु 93,22,89,000/- (तिरानव करोड़ बाईस लाख नवासी हजार) रुपये का बजटीय उपबंध निर्धारित किया गया है ।

14.5.14

4. भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन सहित मानक प्राक्कलन पर कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण, निरीक्षण कगरा एवं परिसर का निर्माण प्रति प्रखंड 12.15 करोड़ (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये की दर से 39 प्रखंडों के लिए 473.85 करोड़ (चार अरब तिहतर करोड़ पचासी लाख रुपये) के लागत व्यय पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 173356 दिनांक 08.01.14 द्वारा लिया जा चुका है।


5. बजट शीर्ष 4059, उप शीर्ष 0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि 93,22,89,000/- (तिरानवे करोड़ बाईस लाख नवासी हजार) रुपये का व्यय वित्त विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश जो पत्रांक 353 दिनांक 15.04.14 एवं पत्रांक 310 दिनांक 28.03.14 में दिया गया है, के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर उक्त मद में वित्त विभाग द्वारा बंधेज अधिसीमा का निश्चित रूप से पालन करते हुये राशि आवंटित की जाय।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे एवं इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

7. उपबंधित राशि के संपूर्ण व्यय के लिए संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उत्तरदायी होंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राशि के प्रत्यर्पण की स्थिति में सकारण प्रतिवेदन वित्त विभाग को भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उनके द्वारा प्रतिवेदित किया जायेगा।

8. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98, पत्र सं0-4981 दिनांक 16.05.13 तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0-7729 दिनांक 26.07.12 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


14.5.14
(अमृत लाल मिश्रा)

प्रधान सचिव

जापांक:- 185396

दिनांक:-

16/05/14

गा0वि0-3/स्था0-13-01/14

प्रतिलिपि- महालेखाकर, बिहार/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

जापांक:- 185396

दिनांक:-

16/05/14

गा0वि0-3/स्था0-13-01/14

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव